



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 138]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 1979/वैशाख 11, 1901

No. 138]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 1979/VAISAKHA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1979

अधिसूचना

आय-कर

सा०का०सि० 282 (अ) :—जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार और भारतीय गणराज्य सरकार के बीच वाणिज्य पोत परिवहन के क्षेत्र में सहकारिता सम्बन्धी उपाबद्ध करार हुआ है;

और उक्त करार के अनुच्छेद 9 में, दोनों राज्यों के पत्तनों के बीच अपने अपने देश के जलयानों द्वारा, जिसके अन्तर्गत सावधि चार्टर के अधीन जलयान भी हैं, वहन किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वीरा पर भाड़ा उपाजनों या लाभों या दोनों से व्युत्पन्न आय पर करों की बाबत बाहरे कराधान से बचने के लिए व्यवस्था है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निदेश करती है कि उक्त करार के उक्त अनुच्छेद के उपबन्धों को भारत संघ में प्रभावी किया जायगा।

अनुबन्ध 1

व्यापारिक नौपरिवहन के क्षेत्र में सहयोग पर जर्मन जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार

जर्मन जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार जिसे हमके बाह्य सचिवाकारी पत्तन कहा गया है :—

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों विशेषकर राष्ट्रों की प्रभुसत्ता की समानता के सिद्धान्त और आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धान्त के अनुसार जर्मन जनवादी गणराज्य तथा भारत गणराज्य के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुवृद्ध करने और व्यापारिक नौपरिवहन के क्षेत्र में विकास करने और सहयोग प्रदान करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद 1

सचिवाकारी पक्ष समान अधिकारों और आपसी लाभ के आधार पर व्यापार नौपरिवहन के क्षेत्र में जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच संबंधों को विकसित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अनुच्छेद 2

इस करार के प्रयोजनों के लिए :—

(क) शब्द 'जहाज' का तात्पर्य होगा सचिवाकारी पक्ष के राष्ट्रीय ध्वज के अन्तर्गत चलने वाला कोई भी व्यापारिक जहाज और क्रमशः जर्मन जनवादी गणराज्य की सीमा और भारत गणराज्य के क्षेत्र में पंजीकृत अथवा दो देशों की राष्ट्रीय नौपरिवहन कम्पनियों द्वारा टाइम चार्टर्ड किया गया हो। इस परिभाषा के अन्तर्गत वे युद्ध पोत और मत्स्य पोत शामिल नहीं हैं जिन पर इस करार के उपबन्ध लागू नहीं होते।

(ख) 'कर्मचाल के सदस्य' का अभिप्रायः होगा उस पोत का मास्टर और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यात्रा के दौरान उस जहाज को चलावे

या संविदा करने के सम्बन्ध में उग पान पर काम करने के लिए नियुक्त हो और कर्मिदल की सूची में शामिल हो।

अनुच्छेद 3

(1) संविदाकारी पक्ष अपनी अपनी राष्ट्रीय विधियों और विनियमों के अनुसार समुद्री कार्यों के लिए जिम्मेदार अपने प्राधिकारियों के बीच सहयोग में और वृद्धि करेंगे। विशेष रूप से, संविदाकारी पक्ष अपने अपने नौपरिवहन संगठनों और उद्यमों के बीच पारस्परिक आधार पर आपसी परामर्श और सूचना के आदान-प्रदान को संबंधित करेंगे।

(2) संविदाकारी पक्ष एक दूसरे के जहाजों को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे और ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे जर्मन जनवादी गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच व्यापारिक नौपरिवहन के विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो।

(3) इस प्रकार की व्यवस्थाएं दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच द्विपक्षीय नौपरिवहन और नौपरिवहन संबंधों पर लागू होंगी।

अनुच्छेद 4

(1) संविदाकारी पक्ष, जर्मन जनवादी गणराज्य और भारत गणराज्य के पत्तनों के बीच विद्यमान नियमित लाइनर नौपरिवहन सेवा जो कि दोनों देशों के बीच सामान्य राष्ट्रीय सामान्य माल की बुलाई की पूर्ति के लिए चलाई जाती है, को मजबूत करने पर सहमत हैं।

संविदाकारी पक्ष, इस बात पर भी सहमत हैं कि दोनों देशों में लाइनर सेवा परिचालन करने वाली राष्ट्रीय नौपरिवहन कम्पनियों को राष्ट्रीय सामान्य माल के उठाने और भाड़े की कमाई में समानता के सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए। इस संबंध में यदि कोई असमानता हो तो उसे वित्तीय आधार पर दोनों प्रत्येक वर्ष के अन्त में निर्धारित किया जायेगा और राष्ट्रीय लाइनों के बीच सहमत कार्याविधि के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

(2) संविदाकारी पक्ष समता और समानता के सिद्धान्तों के आधार पर अपने अपने नौपरिवहन उद्यमों के द्विपक्षीय व्यापार के भारी राष्ट्रीय माल की बुलाई करने में भाग लेने पर सहमत हैं।

द्विपक्षीय व्यापार के भारी माल की बुलाई संबंधों का ब्यौंग संविदाकारी पक्षों द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित सक्षम संगठनों द्वारा निर्धारित कर लिया जायेगा।

(3) यदि किसी संविदाकारी पक्ष को नौपरिवहन कम्पनियां इस अनुच्छेद की व्यवस्थाओं के अनुसार माल की बुलाई करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी बुलाई दूसरे संविदाकारी पक्ष के जहाजों को दे दी जाएगी। यदि वह संविदाकारी पक्ष स्वीकार्य शर्तों पर अपेक्षित टन भार उपलब्ध नहीं करा सकती तो पहले संविदाकारी पक्ष को तीसरे देश के छवज के अन्तर्गत माल के अपने भाग के लिए जहाजों के प्रयोग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 5

(1) एक संविदाकारी पक्ष के जहाज, उनके कर्मिदल और माल पर वही शर्तें लागू होंगी, जो किस वार्षिक अनुकूल राष्ट्र के जहाजों कर्मिदल तथा माल के अन्य संविदाकारी पक्ष के पत्तनों में प्रवेश रवानगी अथवा पड़ाव के दौरान लागू होती है।

(2) एक संविदाकारी पक्ष के जहाज, कर्मिदल यात्री और माल पर दूसरे संविदाकारी पक्ष की सीमा के भीतर होने के दौरान बाध में लिखे गए संविदाकारी पक्ष की विधियां नियमों और विनियम लागू होंगे।

(3) इस करार की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत परिचालित जहाजों की सेवाओं पर सभी पत्तन शुल्क और प्रभार संबंधित पत्तनों पर समय समय पर लागू राष्ट्रीय विधियों और विनियमों के अनुसार विनियमित किए जायेंगे।

(4) इस अनुच्छेद की व्यवस्थाएं प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा अपने संगठनों अथवा उद्यमों के लिए कानूनी तौर से नियत की गयी विधि-विधियों पर लागू नहीं होंगी जिनमें विशेषकर राष्ट्रीय नौचालन और पायनेट सेवा शामिल है और इससे विदेशियों के प्रवेश और ठहराव संबंधी नियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 6

संविदाकारी पक्ष अपने एवं राष्ट्रीय विधियों और विनियमों की सीमा के भीतर समुद्री यातायात को आगे बढ़ाने और उसे सुविधाजनक बनाने जलपोंतों के विनम्व को रोकने और पत्तनों पर अपेक्षित सीमा शुल्क संबंधी तथा अन्य औपचारिकताओं को सरल एवं यथामंभय रूप में कम करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय बरतेंगे।

अनुच्छेद 7

(1) जल पोंतों की राष्ट्रीयता और पंजीकरण प्रत्येक से संबंधित टन भार प्रमाणपत्र समुद्री योग्यता का प्रमाणपत्र तथा जहाज के अन्य प्रत्येक जो कि एक संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अथवा स्वीकृत किए गए हों—को मान्यता दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दी जायेगी।

(2) एक संविदाकारी पक्ष के जलपोंतों जिनके पाम विधिवत् जारी किए गए टन भार प्रमाणपत्र हों की अन्य संविदाकारी पक्ष के पत्तनों पर पुनः माप-तोला नहीं की जायेगी।

अनुच्छेद 8

(1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए नाविक पहचान-प्रलेखों को मान्यता देगा।

“नाविक पहचान प्रलेख ये हैं :—

—जर्मन जनवादी गणराज्य के नागरिकों के लिए

“सी फर्स्टबुच डर ड्युस्वेन डेमाकेटिसधेन रिपब्लिक”

—भारतीय जलपोंतों के नाविकों के लिए “कन्टोम्पूअस हिस्वाजै सर्टिफिकेट”

(2) जलपोंतों के कर्मिदल के सदस्यों के मामले में उपरोक्त पैरा 1 में विनिर्दिष्ट नाविक पहचान-प्रलेख-धारियों को अन्य संविदाकारी पक्ष में जलपोंत के पड़ाव के दौरान बीसा के बिना अस्थायी तट अवकाश पर उतरने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि मास्टर ने उस पत्तन पर लागू विनियमों के अनुसार कर्मिदल की सूची सक्षम प्राधिकारियों को पेश कर दी हो।

जलपोंत से उतरने और उसमें वापस लौटते समय उक्त व्यक्तियों पर उस पत्तन पर लागू सीमांत और भीमाशुल्क नियंत्रण लागू होंगे।

(3) जब कर्मिदल का कोई सदस्य जिसके पास पहचान-प्रलेख और निर्धारित अनुमति-पत्र हो बीमारी के कारण कार्यालय संबंधी कारण अथवा अन्य किसी कारण से दूसरे संविदाकारी पक्ष के पत्तन में जहाज से उतरता है तो दूसरा पक्ष उस व्यक्ति को किसी अन्य हस्पताल में भर्ती कराने उसे स्वदेश प्रत्यावर्तित कराने या वापस लौटने अथवा किसी अन्य जलपोंत में समायोजन के लिए उसे किसी अन्य पत्तन में भिजवाने की अनुमति देगा। पहचान प्रलेखों के साथ नौ परिवहन संगठनों के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ मुहरबन्ध और विधिवत हस्ताक्षरयुक्त अथवा जलपोंत के मास्टर द्वारा अपने हस्ताक्षर सहित जारी किया हुआ कार्यालय आदेश लगाना अनिवार्य होगा।

(4) नाविक पहचान प्रलेख धारियों को किसी भी परिवहन साधन के द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में प्रवेश करने और आने जाने

की अनुमति होगी ताकि वे संबंधित संविदाकारी पक्ष के समुचित प्राधिकारियों की स्वीकृति से दूसरे संविदाकारी पक्ष के पत्तन में अपने देश के जलयोत में जा सकें। ऐसे सभी मामलों में नाविक के पास दूसरे संविदाकारी पक्ष का समुचित बीमा अवश्य होना चाहिए जो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यथासंभव कम से कम समय के भीतर दे दिया जाएगा।

(5) नौपरिवहन कानूनों के विनियमन के लिए, दूसरे संविदाकारी पक्ष के पत्तन में ठहरने वाले जलयोत के मास्टर को या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को नौवहन कम्पनी के कौन्सिली अधिकारी या प्रतिनिधि से संपर्क करने या उससे बैठ कराने की अनुमति दी जाएगी।

अनुच्छेद 9

जर्मन जनवादी गणराज्य की सरकार टाइम-चाटर जलयोतों सहित अन्य भारतीय जलयोतों द्वारा दोनों राज्यों के पत्तनों के बीच जाए, ले जाए गए राष्ट्रीय माल से होने वाली भाड़ा कमाई और/अथवा लाभ पर कोई आयकर और/अथवा उत्पादन कर नहीं लगाएगी या एकत्र करेगी तथा उसी प्रकार भारत गणराज्य की सरकार जर्मन जनवादी गणराज्य के टाइम चाटर जलयोतों सहित अन्य जलयोतों द्वारा दोनों राज्यों के पत्तनों के बीच जाए, ले जाए गए राष्ट्रीय माल से होने वाली भाड़ा कमाई और/अथवा लाभ पर कोई आय कर और/अथवा उत्पादन कर नहीं लगाएगी या एकत्र करेगी।

अनुच्छेद 10

(1) दूसरे संविदाकारी पक्ष की नौपरिवहन कम्पनियों के जलयोतों की आवश्यकताओं की देखभाल के लिए प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने नियमों तथा विनियमों के अनुसार अपने प्रदेश में दूसरे संविदाकारी पक्ष के नौपरिवहन संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों की स्थापना करने की अनुमति देगा। उक्त प्रतिनिधि-मण्डल तथा उनके कर्मचारियों को वे सभी अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त होंगी जो सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र के तदरूप प्रतिनिधि-मंडलों तथा उनके कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं।

(2) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने देश में लागू नियमों तथा विनियमों के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में स्थित कार्यालयों सहित नौवहन उद्यमों के प्रतिनिधियों की अपने समुद्री पत्तनों में निबांध प्रवेश करने की अनुमति देगा ताकि वे जलयोतों कर्मचिल तथा माल की देखभाल के संबंध में अपने सरकारी कार्य कर सकें और साथ में, वह उन्हें जलयोत में चढ़ने की अनुमति भी देगा।

अनुच्छेद 11

(1) अगर दोनों में से किसी एक संविदाकारी पक्ष कोई जलयोत अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्य के क्षेत्र के भीतर विध्वंस हो जाता है, जमीन में धंस जाता है, फिनारे पर जा पड़ता है या किसी अन्य दुर्घटना में प्रस्त हो जाता है तो बाव के संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में विद्यमान ऐसे जलयोत, उसके कर्मचिल यान्त्री तथा माल को वहीं सहायता प्रदान की जाएगी जो वह संविदाकारी पक्ष अपने देश के जलयोत कर्मचिल यान्त्री तथा माल को प्रदान करता है।

(2) कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के इस प्रकार ध्वस्त हुए जलयोत इसके माल या सामान पर तब तक कोई सीमाशुल्क नहीं लगाएगा जब तक वे प्रयोजनसिद्ध संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में प्रयोग हेतु नहीं सौंप दिए जाते।

(3) इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध से संविदाकारी पक्षों के नियमों तथा विनियमों पर और उनके अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के व्यवहार पर कोई रोक नहीं आएगी।

अनुच्छेद 12

इस करार के अधीन जलयोतों के परिचालन से उत्पन्न होने वाले सभी खर्चों और अदायगियों का भुगतान समय-समय पर लागू होने वाले संविदाकारी पक्षों के बीच सम्पन्न व्यापार एवं अदायगी करारों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

अनुच्छेद 13

(1) इस करार के समग्र कार्य का मूल्यांकन पर्यवेक्षण तथा पुनरीक्षण करने के लिए तथा किसी भी विवादग्रस्त विषय को सुझने के लिए संविदाकारी पक्ष एक अन्तर सरकारी नौवहन संयुक्त समिति की स्थापना करने पर सहमत हैं, जो जितनी बार आवश्यक समझा गया उसनी बार जर्मन जनवादी गणराज्य में और भारत गणराज्य में बारी-बारी से अपनी बैठक करेगी। जर्मन जनवादी गणराज्य का परिवहन मंत्रालय तथा भारत गणराज्य का नौवहन और परिवहन मंत्रालय इस संयुक्त समिति में अपने प्रतिनिधियों को नामजद करेगा।

(2) ती ई श्री ड्यूवरैचट/सोरीदेरेई रोस्टांक तथा भारतीय नौवहन निगम लि० बम्बई गश्म संगठन होंगे जिन्हें माय के वितरण जल पोतों की रवानगी के निर्धारण दैनिक संबंधी मामले, तथा उनके कार्यों से उत्पन्न होने वाले इसी प्रकार के अन्य मामलों जैसे दोनों राज्यों के बीच दिन प्रतिदिन उठने वाले नौवहन परिचालन संबंधी विषयों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को अधिसूचना देकर उपरोक्त संगठन के अलावा किसी अन्य संगठन को भी नामजद कर सकता है।

अनुच्छेद 14

संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि उनके गश्म प्राधिकारी समुद्री यातायात के क्षेत्र में ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा करारों से संबंधित सभी मामलों पर जिनमें दोनों संविदाकारी पक्षों की अभिरूचि हो, एक दूसरे से परामर्श करेंगे। विशेषतया इसका संबंध समुद्री यातायात के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और अभिसमयों (कन्वेंशनों) में सहयोग से है।

अनुच्छेद 15

समुद्री कानून और नौपरिवहन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों से उत्पन्न होने वाले संविदाकारी पक्षों के अधिकारों तथा दायित्वों पर इस करार के उपबंधों का प्रभाव नहीं पड़ता।

अनुच्छेद 16

इस करार की व्याख्या या प्रयोज्यता के बारे में उत्पन्न मतभेदों का समाधान अनुच्छेद 13 के पैरा 1 वर्णित अन्तर्संरकारी नौवहन संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा। यदि उक्त संयुक्त समिति किसी प्रश्न पर सहमत न हो पाए तो उस प्रश्न का समाधान संबंधित सरकारों को पत्र लिखकर किया जाएगा।

अनुच्छेद 17

(1) यह करार अपने लागू होने की तारीख से व्यापार नौवहन के क्षेत्र में दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच हस्ताक्षर किए गए पहले के सभी करारों का अधिक्रमण करता है।

(2) दोनों संविदाकारी पक्षों के राज्यों में गश्म संस्थाओं और संगठनों तथा राष्ट्रीय नौवहन कम्पनियों के बीच पहले के सभी वाणिज्यिक स्तर के प्रबंध जारी रहेंगे बशर्ते कि वे इस करार के उपबंधों के विरुद्ध न पड़ें हों।

अनुच्छेद—18

(1) यह करार राष्ट्रीय नियमों तथा विनियमों के अनुसार इस करार के अनुमोदन को सूचित करने वाले पक्षों के आदेश प्रदान के 30 दिन बाद लागू हो जाएगा।

(2) यह करार पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। इसके बाद यह स्वतः एक बार में एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ता जाएगा जब तक कि दोनों संविदाकारी पक्षों में से कोई एक पक्ष उक्त अवधि की समाप्ति से कम से कम छः माह पूर्व करार को भंग करने की निम्नित सूचना न दे दे।

इस माध्य में, अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने जिन्हें उनको अपनी-अपनी सरकारों ने यथोचित अधिकार दिया है इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह करार नई दिल्ली में तारीख 9-1-1979 को जर्मन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक भाषा की दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न हुआ सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे। जर्मन और हिन्दी पाठों में कोई गलती होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

जर्मन जनवादी गणराज्य

भारत गणराज्य की सरकार

की सरकार से लिए

के लिए

अनुबंध—I

नई दिल्ली

9 जनवरी, 1979

महामहिम,

मैं सावर आपका ध्यान भारत गणराज्य की सरकार और जर्मन जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच व्यापार नौवहन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार के अनुच्छेद 12 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस करार के अनुच्छेद 3 के खण्ड 3 के साथ पठित, अनुच्छेद 12 में यह व्यवस्था है कि उक्त करार के अन्तर्गत, दोनों देशों के बीच जहाजों के परिचालन में होने वाले सभी भुगतान और व्यय दोनों देशों के बीच व्यापार और भुगतान करार के उन उपबंधों के अनुसार किए जाएंगे जो इस समय लागू हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह खण्ड दोनों देशों के बीच माल की दुलाई में बाड़े से होने वाली आय और व्यय के भुगतान के लिए ही लागू होगा।

यदि आप यह पुष्टि कर दें कि भारत सरकार और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच जो समझौता हुआ है वह ऊपर लिखे हुए के ठीक अनुरूप है तो मैं आपका अत्यन्त आभारी होऊंगा।

अत्यन्त सम्मान के साथ।

आपका शुभचिन्क

हस्ता०

(चाँद राम)

नौवहन और परिवहन मंत्री

भारत सरकार।

अनुबंध—II

नई दिल्ली

9 जनवरी, 1979

महामहिम,

आपका 9 जनवरी, 1979 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसका पाठ इस प्रकार है:

“मैं सावर आपका ध्यान भारत गणराज्य की सरकार और जर्मन जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच व्यापार नौवहन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार के अनुच्छेद 12 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस करार के अनुच्छेद 3 के खण्ड 3 के साथ पठित, अनुच्छेद 12 में यह व्यवस्था है कि उक्त करार के अन्तर्गत, दोनों देशों के बीच जहाजों के परिचालन में होने वाले सभी भुगतान और व्यय दोनों देशों के बीच व्यापार और भुगतान करार के उन उपबंधों के अनुसार किए जाएंगे जो इस समय लागू हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह खण्ड दोनों देशों के बीच माल की दुलाई में बाड़े से होने वाली आय और व्यय के भुगतान के लिए ही लागू होगा।”

“यदि आप यह पुष्टि कर दें कि भारत सरकार और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच जो समझौता हुआ है वह ऊपर लिखे हुए के ठीक अनुरूप है तो मैं आपका अत्यन्त आभारी होऊंगा।”

मैं इस बात की सावर पुष्टि करता हूँ कि आपके पत्र का पाठ जर्मन जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के ठीक अनुरूप है।

अत्यन्त सम्मान के साथ।

आपका,

हस्ता०

(प्रोसकर फिशर)

जर्मन जनवादी गणराज्य

के विदेश मंत्री

महामहिम श्री मान चाँद राम,

नौवहन और परिवहन मंत्री,

भारत सरकार।

[का० सं० 11/3/69-गफ०टी०बी]

जगदीश चन्द्र कानरा

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 27th April, 1979

G.S.R. 282(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of German Democratic Republic and the Government of the Republic of India on Co-operation in the Field of Merchant Shipping has been concluded;

And whereas Article 9 of the said Agreement provides for the avoidance of double taxation in respect of taxes on income derived from the freight earnings or profits or both on national cargo carried by the vessels of the respective countries including those under time-charter between ports of the two States;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Article of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE I

AGREEMENT

Between the Government of the German Democratic Republic and the Government of the Republic of India on Co-operation in the Field of Merchant Shipping.

The Government of the German Democratic Republic and the Government of the Republic of India (hereinafter called the Contracting Parties);

Being desirous of,

Strengthening the friendly relations between the German Democratic Republic and the Republic of India according to the principles of international law, especially the principle of sovereign equality of States and the principle of non-interference in internal affairs; and Developing and extending co-operation in the field of merchant shipping:

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties agreed to develop the relations between the German Democratic Republic and the Republic of India in the field of merchant shipping on the basis of equal rights and mutual benefit.

Article 2

For the purposes of this Agreement:

(a) The term “vessel” shall mean any merchant vessel Plying under the national flag of a Contracting Party

and registered in the territory of the German Democratic Republic and in the territory of the Republic of India respectively or time chartered by the national shipping companies in the two States.

This definition excludes warships and fishing vessels from the scope of application of this Agreement.

- (b) The term "member of the crew" shall mean any person actually employed for duties on board during a voyage in connection with the operation or service of the vessel and included in the crew list.

Article 3

(1) The Contracting Parties shall further develop cooperation between their authorities responsible for maritime affairs according to their respective national laws and regulation. In particular, the Contracting Parties shall promote mutual consultations and exchange of information on reciprocal basis between these authorities as well as cooperation between the respective shipping organisations and enterprises.

(2) The Contracting Parties shall grant all possible assistance to each other's vessels and shall not take any action which may cause hindrance for the development of merchant shipping between the German Democratic Republic and the Republic of India.

(3) The provisions of this Agreement shall be applicable to bilateral shipping and shipping relations between the two Contracting Parties.

Article 4

(1) The Contracting Parties agree to strengthen the existing regular liner shipping service between the ports of the German Democratic Republic and the ports of the Republic of India to cater for the movement of national general cargo between the two States.

The Contracting Parties further agree that the national shipping companies in the two States operating bilateral liner shipping service should observe the principle of parity in loadings of national general cargoes and freight earnings thereof. Imbalance, if any, in this respect, shall be determined in financial terms at the end of each year and settlement effected in accordance with the procedure agreed among the national lines.

(2) The Contracting Parties agree to the participation of their respective shipping enterprises in the carriage of national bulk cargoes in the bilateral trade on the principles of parity and equality.

Details of arrangements concerning the carriage of bulk cargoes in the bilateral trade shall be worked out by the competent organisations to be nominated for this purpose by the Contracting Parties.

(3) In case the shipping companies of one of the Contracting Parties are not able to undertake the carriage in accordance with the provisions of this Article, such carriage will be offered to vessels of the other Contracting Party. If that Contracting Party cannot make available the required suitable tonnage on acceptable conditions, the first mentioned Contracting Party is entitled to use vessels under the flag of third countries for the carriage of its share of cargo.

Article 5

(1) The vessels of one Contracting Party and their crew and cargo shall be subject to the same conditions as ships, crew and cargo of the most-favoured nation when entering into, sailing from or staying in the ports of the other Contracting Party.

(2) The vessels, crew, passengers and cargo of one Contracting Party, whilst within the territory of the State of the other Contracting Party, shall be subject to laws, rules and regulations of the latter mentioned Contracting Party.

(3) All port dues and charges for services rendered to the vessels operating under the provisions of this Agreement shall be regulated in accordance with the national laws and regulations applicable at the respective ports from time to time.

(4) The provisions of this Article shall not apply to activities legally reserved by each of the Contracting Parties to its organisations or enterprises including, in particular, coastal navigation and pilot service and also shall not affect the rules concerning entry and stay of foreigners.

Article 6

The Contracting Parties shall adopt within the limits of their concerned national laws and regulations all appropriate measures to facilitate and expedite maritime traffic, to prevent delays to vessels and to simplify and expedite as much as possible the carrying out of customs and other formalities required in ports.

Article 7

(1) The documents relating to nationality and registration of vessels, tonnage certificates, certificates of seaworthiness and other ship documents issued or recognised by the competent authorities of one Contracting Party shall be recognised by the competent authorities of the other Contracting Party.

(2) Vessels of one Contracting Party in possession of duly issued tonnage certificates shall not be subject to re-measurement in the ports of the other Contracting Party.

Article 8

(1) Each of the Contracting Parties shall recognise the seamen's identity documents issued by the competent authorities of the other Contracting Party.

These seamen's identity documents are :

- for nationals of the German Democratic Republic "Seefahrtbuch der Deutschen Demokratischen Republik".
- for seamen of the Indian vessels "Continuous Discharge Certificate".

(2) Holders of the seamen's identity documents specified in paragraph 1 above shall be permitted in the case of members of the crew of the vessel to land on temporary shore leave without visa during stay of the vessel in port of the other Contracting Party, provided that the master had submitted the crew list to the competent authorities in accordance with the regulations in force in that port. While landing and returning to the vessel, the said persons shall be subject to frontier and customs control in force in that port.

(3) When a member of the crew possessing an identity document and the prescribed permission, disembarks in the port of the other Contracting Party due to illness, official reasons or other reasons, the latter shall allow his being put up at a hospital, his being repatriated or returning to his home country or his being moved to another port in order to be accommodated in another vessel. The identity documents shall be accompanied by an official order issued, under seal and signature, by the competent officer of the shipping organisations or by the master of the vessel under his signature.

(4) Holders of the seamen's identity documents shall be permitted to enter, move through by any means of transport in the territory of the other Contracting Party in order to be able to join a vessel of their country in a port of the other Contracting Party with the approval of the appropriate authorities of that Contracting Party. In all such cases, the seamen shall be required to have proper visa of the other Contracting Party which shall be granted by the concerned authorities within the shortest possible time.

(5) For the purpose of regulation of shipping affairs, the master of the vessel staying in the port of the other Contracting Party or a person authorised by him shall be permitted to contact or visit the consular official or the representative of the shipping company.

Article 9

No income tax and/or turnover tax shall be levied or collected by the Government of the German Democratic Republic on the freight earnings and/or profits on national cargo carried by the Indian vessels including those under time-charter between ports of the two States, and similarly no income tax and/or turnover tax shall be levied or collected

by the Government of the Republic of India on the freight earnings and/or profits on national cargo carried by the vessels of the German Democratic Republic including those under time-charter between ports of the two States.

Article 10

(1) Each Contracting Party shall allow in its territory the establishment of representations of the shipping organisations of the other Contracting Party for looking after the requirements of the vessels of the shipping companies of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations. The said representations and their personnel shall enjoy the same rights and privileges which are granted to similar representations and their personnel of the most favoured nation.

(2) Each Contracting Party shall grant to the representatives of shipping enterprises with offices in the territory of the other Contracting Party unhindered entry into its sea ports, according to the national laws and regulations in force, in order to enable them to perform their official duties with regard to the care of vessels, crew and cargo and shall permit them to board vessels.

Article 11

(1) If a vessel of one of the Contracting Parties suffers shipwreck, runs aground, is cast ashore or suffers any other accident within the territory of the State of the other Contracting Party, the vessel, the crew, the passengers and the cargo shall receive, in the territory of the latter Contracting Party, the same assistance which is accorded by that Contracting Party to its national vessel, crew, passengers and cargo.

(2) VEB Deufracht/Seereederei, Rostock and the Shipping Party against a shipwrecked vessel, its cargo or store of the other Contracting Party unless they are delivered for use in the territory of the first-mentioned Contracting Party.

(3) Nothing in the provisions of this Article shall prevent the application of the laws and regulations of the Contracting Parties and their international obligations.

Article 12

All payments and expenses under this Agreement arising from the operation of vessels shall be made according to the provisions of the Trade and Payments Agreement between the Contracting Parties that may in force from time to time.

Article 13

(1) For the purpose of evaluating, supervising and reviewing the overall working of this Agreement and resolving any outstanding issues, the Contracting Parties agree to set up an Inter-Governmental Joint Committee on Shipping which will meet as often as necessary, in the German Democratic Republic and in the Republic of India, alternatively. The Ministry of Transport of the German Democratic Republic and the Ministry of Shipping and Transport of the Republic of India will nominate their representatives to the Joint Committee.

(2) VEB Deufracht/Seereederei, Rostock and the Shipping Corporation of India Ltd., Bombay will be the competent organisations authorised to deal with day-to-day shipping operational issues between the two States, such as distribution of cargoes, fixation of sailings, tariff matters and similar other issues arising out of their operations. Each Contracting Party may nominate any other organisation in addition to the above by notifying to the other Contracting Party.

Article 14

The Contracting Parties agree that their competent authorities will consult each other in all matters relating to international Conferences and Agreements in the field of maritime traffic in which both Contracting Parties are interested. In particular, this relates to co-operation in International Organisations and Conventions in the field of maritime traffic.

Article 15

The provisions of this Agreement do not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising out of International Conventions on maritime law and shipping.

Article 16

Any differences of opinion with regard to interpretation or application of this Agreement shall be settled by the Inter-governmental Joint Committee on Shipping mentioned in Article 13, para 1. In case the said Joint Committee is unable to come to an agreement on any issue, the same shall be settled by reference to the respective Governments.

Article 17

(1) This Agreement supersedes all previous Agreements signed between the two Contracting Parties in the field of merchant shipping with effect from its entry into force.

(2) All the previous commercial level arrangements between the competent institutions and organisations and the national shipping companies in the States of the two Contracting Parties shall continue to remain in force insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Agreement.

Article 18

(1) This Agreement shall enter into force 30 days after the exchange of notes signifying the approval of the Agreement in accordance with the national laws and regulations.

(2) This Agreement shall be valid for a period of five years. It shall be automatically renewed for a further one-year period at a time unless either of the Contracting Parties gives written notice of termination of the Agreement not later than six months before the expiry of such period.

In witness whereof, the undersigned duly empowered by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at New Delhi on 9th January, 1979 in two originals each in German, Hindi and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any discrepancy in the German and Hindi texts, the English text shall prevail.

Sd/-

(CHAND RAM).

For the Government of the German Democratic Republic.

Sd/-

(OSKAR FISCHER).
For the Government of the Republic of India

ANNEXURE I
New Delhi,
9th January, 1979

Excellency,

I have the honour to invite your attention to Article 12 of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the German Democratic Republic on co-operation in the field of merchant shipping. Article 12 reads with clause 3 of Article 3 of this Agreement provides that all payments and expenses, under the said Agreement arising from the operation of vessels between the two countries shall be made according to the provisions of Trade and Payments Agreement between the two countries that may be in force for the time being. This is to clarify that this clause would be applicable only in respect of payment of freight earnings and expenses arising from the carriage of cargo between the two countries.

I shall be grateful if you kindly confirm that the above correctly sets out the understanding reached between the Government of India and the Government of the German Democratic Republic.

Assuring you of my highest consideration,

Yours sincerely,

Sd./ CHAND RAM,
Minister of Shipping and Transport
Government of India.

His Excellency Mr. Oskar Fischer,
Minister of External Affairs
of the German Democratic Republic,
New Delhi.

ANNEXURE II
New Delhi,
9th January, 1979.

I shall be grateful if you kindly confirm that the above correctly sets out the understanding reached between the Government of India and the Government of the German Democratic Republic."

Excellency,

I acknowledge the receipt of your letter of 9th January, 1979 which reads as follows :

"I have the honour to invite your attention to Article 12 of the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the German Democratic Republic on co-operation in the field of merchant shipping. Article 12 reads with clause 3 of Article 3 of this Agreement provides that all payments and expenses, under the said Agreement, arising from the operation of vessels between the two countries shall be made according to the provisions of Trade and Payments Agreement between the two countries that may be in force for the time being. This is to clarify that this clause would be applicable only in respect of payment of freight earnings and expenses arising from the carriage of cargo between the two countries.

I have the honour to confirm that the contents of your letter correctly set out the understanding reached between the Government of the German Democratic Republic and the Government of India.

Assuring you of my highest consideration,

Yours sincerely,
Sd/- OSKAR FISCHER,
Minister of External Affairs,
of the German Democratic Republic.

His Excellency Mr. Chand Ram,
Minister of Shipping and Transport,
Government of India.
New Delhi.

J. C. KALRA, Jt.Secy.
[F. No. 11/3/69-FTD]

